स्वास्थ्य हो प्राथमिकता

पिछले दो दशकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को समेकित रूप से सक्षम बनाने के लिए अनेक अहम पहलें की है. हालांकि, इनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं, परंतु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है. पिछले साल वाशिंगटन विवि द्वारा जारी 'ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिजीजेज' रिपोर्ट में जानकारी दी गयी थी कि 2017 में लगभग 91 लाख मौतें हुई थीं, जिनमें से तकरीबन 90 फीसदी का संबंध स्वास्थ्य से जुड़े कारणों से था. हमारे देश में इस मद पर सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद आज भी कुल घरेलू उत्पादन का सवा फीसदी के आसपास ही है, जो दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है. दक्षिण एशिया के अनेक पड़ोसी देश इससे अधिक निवेश करते हैं. वैसे 2010 की तुलना में 2018 का स्वास्थ्य बजट दोगुना हो चुका था, पर इलाज का 62 फीसदी खर्च लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ता है. सरकारी अस्पतालों के अभाव तथा कुप्रबंधन के कारण लोगों को शहरों में स्थित निजी क्षेत्र की चिकित्सकीय सुविधाओं की शरण लेनी पड़ती है. देश में 95 फीसदी से अधिक केंद्रों में कार्यरत लोगों की संख्या पांच से कम है. इस स्थिति में बदलाव कर असमय काल-कवलित हो रहे लोगों को बचाया जा सकता है. बीमा योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं में सामंजस्य की कमी भी एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के त्वरित प्रसार की दरकार है. इसके अंतर्गत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों के होने से बीमारियों को जानलेवा होने से रोका जा सकता है तथा इससे लोगों और सरकार का वित्तीय दबाव भी कम होगा. इस योजना में बीमा के जरिये उपचार के बड़े खर्चों के बोझ से गरीब और कम आमदनी वर्ग को राहत दी जा रही है. इसके कार्यान्यवयन को सुचारू बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को स्थापित करने की प्रक्रिया भी तेज की जानी चाहिए. एक तरफ गंभीर बीमारियों के उपचार की व्यवस्था तथा मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी पर जोर दिया जाना चाहिए, वहीं मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण, आयुष का विस्तार, पोषण बढ़ाने, स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता जैसी पहलों को अधिक निवेश व दक्ष कर्मियों की भर्ती से अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए. एक समेकित नीतिगत और व्यावहारिक पहल सरकार के पिछले कार्यकाल में हो चुकी है. उम्मीद है कि स्वास्थ्य के मद में जीडीपी के ढाई फीसदी खर्च करने के इरादे को पूरा करने की प्रक्रिया आगामी केंद्रीय बजट में शुरू हो जायेगी. बीमारियां, दुर्घटनाएं और अवसाद पर अंकुश लगाकर लाखों मौतों को टाला जा सकता है. इससे परिवार, समाज और देश को विकास एवं समृद्धि की राह पर अग्रसर होने में बड़ी मदद मिलेगी.

बीमारियां, दुर्घटनाएं और अवसाद पर अंकुश लगाकर लाखों मौतों को टाला जा सकता है. इससे देश को विकास एवं समृद्धि की राह पर अग्रसर होने में बड़ी मदद मिलेगी.

गंभीर संकट के दौर में कांग्रेस

नवीन जोशी
वरिष्ठ पत्रकार
naveengjoshi@gmail.com

लोकतंत्र की अच्छी सेहत के लिए आवश्यक है कि सशक्त विपक्ष मौजूद हो. सत्तारूढ़ दल के पास प्रचंड बहुमत हो, तो उसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है, ताकि सत्ता के निरंकुश होने की संभावना टाली जा सके. सशक्त विपक्ष बहुमत वाली सरकार को संविधान की मंशा के दायरे में ही कार्य करने के लिए नकेल का काम करता है.

बीते आम चुनाव में नरेंद्र मोदी एक 'कल्ट' के रूप में उभरे हैं. उन्हीं की छवि से अकेले भाजपा को तीन सौ से ज्यादा और एनडीए को साढ़े तीन सौ सीटें मिली हैं. देश के अधिसंख्य राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन की सरकारें हैं. राज्यसभा में अभी सत्तारूढ़ दल बहुमत में नहीं है, लेकिन एक साल में यह भी उसे हासिल हो जायेगा. तब सरकार अपने मनचाहे विधेयक पारित करा सकती है.

इन हालात में सशक्त विपक्ष की बड़ी जरूरत है, जो न केवल सरकार पर चौकस निगाह रख सके, बल्कि स्वस्थ और रचनात्मक आलोचना से उसकी सहायता भी कर सके. आज हमारे पास सशक्त विरोधी दल तो छोड़िए, लोकसभा में आधिकारिक प्रतिपक्ष के रूप में भी कोई पार्टी नहीं है. ले-देकर कांग्रेस है, लेकिन वह 2014 में जीती मात्र 44 सीटों को इस बार 52 तक ही ले जा सकी. ये उतनी भी सीटें नहीं हैं कि लोकसभा में उसके नेता को प्रतिपक्ष के नेता का संवैधानिक दर्जा मिल सके.

यहां यह भी कहना है कि संख्या बल ही सशक्त विपक्ष की गारंटी नहीं है. नेहरू-युग में जब कांग्रेस बहुत ताकतवर थी और कोई दूसरा राष्ट्रीय दल उनके आस-पास भी नहीं था, तब विपक्ष के कई धुरंधर नेता अकेले दम पर कांग्रेस सरकार पर अंकुश रखने में सफल थे. लोहिया का गैर-कांग्रेसवाद उसी दौर की उपज था. 1971 की प्रचंड विजय के बाद जब इंदिरा गांधी निरंकुश होती गयीं और 1975 में उन्होंने देश पर आपातकाल थोप कर संविधान को निलंबित कर दिया, तब छोटे-छोटे दलों ने एक होकर उन्हें जबरदस्त चुनौती दी और सत्ता से बाहर किया. कांग्रेसी वर्चस्व को संयुक्त विपक्ष की सशक्त चुनौतियां मिलने के एकाधिक उदाहरण ताजा इतिहास में हैं.

क्या आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि वह मोदी सरकार को, जो और भी शक्तिशाली होकर सत्ता में लौटी है, संसद से सड़क तक चुनौती दे सके? पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे 52 एमपी मोदी सरकार को चैन से बैठने नहीं देने के लिए काफी हैं. ऐसा हो सके तो लोकतंत्र के लिए शुभ होगा, लेकिन क्या आज कांग्रेस की हालत देखकर उनकी बात पर भरोसा होता है?

सोलहवीं लोकसभा में जब कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गयी थी, तो कहा गया था कि वह अपने सबसे कठिन दौर में है. सत्रहवीं लोकसभा में उसके आठ और सांसद जीतकर आ गये. इसके बावजूद कांग्रेस अब कहीं ज्यादा गंभीर संकट से गुजर रही है. देश की यह सबसे पुरानी और गहरी जड़ों वाली पार्टी फिर कैसे खड़ी होती है, यह समय बतायेगा, लेकिन फिलहाल पुराने खांटी कांग्रेसी नेता पार्टी के भविष्य के प्रति चिंतातुर हैं.

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली ने कुछ दिन पहले यूं ही नहीं कहा कि राहुल गांधी या तो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लें या कोई सुयोग्य विकल्प दें, लेकिन कांग्रेस के भीतर का असंतोष तत्काल दूर करने के उपाय करें. उनकी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं की चिंता के पर्याप्त कारण हैं. तेलंगाना में कांग्रेस के 12 विधायक सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो गये. महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल में टूट के आसार हैं. कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर घमासान जारी है, विधायक पाला-बदल कर रहे हैं और जद (एस) गठबंधन तोड़ने की धमकी तक दे चुका है.

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुलेआम लड़ रहे हैं. मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों को खुद कांग्रेसी विधायक कब अल्पमत में ले आयें, कहा नहीं जा सकता. एकमात्र कांग्रेसी राज्य पंजाब में, जो मोदी लहर को रोकने में कामयाब रहा, कांग्रेस के भीतर लड़ाई चल रही है. उत्तर-पूर्व के राज्यों में ज्यादातर पुराने कांग्रेसी पार्टी छोड़ चुके हैं. उत्तर प्रदेश में दो साल से पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है. बिहार में भी विधायक दल में असंतोष की खबरें आती रहती हैं. जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, झारखंड सभी जगह आपसी लड़ाइयां हैं. कोई राज्य ऐसा नहीं, जहां कांग्रेस आज बेहतर संगठन और सक्रियता के लिए जानी जाती हो.

पार्टियों में असंतोष और झगड़े नयी बात नहीं हैं. भाजपा में भी कई राज्यों में बहुत असंतोष हैं, लेकिन वहां पार्टी नेतृत्व उसे नियंत्रित करने में देर नहीं लगाता. कांग्रेस नेतृत्व ने हाल में किसी राज्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लगे कि वह संगठन की समस्याओं के समाधान के लिए सजग और सक्रिय है.

चुनावों में बड़ी पराजय के बाद से राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कोप-भवन में हैं. कुछ नेता उन्हें मनाने में लगे हैं. उधर पार्टी बिखर रही है. राहुल के अलावा किसी और को अध्यक्ष चुनना हो, तो वह निर्णय बहुत ही जल्द किया जाना चाहिए. समस्या यह है कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस इस कदर नेहरू-गांधी वंश पर आश्रित होती गयी कि आज के कांग्रेसी उस परिवार के सदस्य के अलावा किसी और को अपना नेता चुनने की कल्पना तक नहीं कर सकते.

राहुल गांधी करें या कोई और, कांग्रेस को अपना घर संभालते हुए न केवल नये सिरे से खड़ा करना है, बल्कि उनकी मुख्य चुनौती उस विचार को देशभर में फिर से प्रसारित करने की है, जिसे वह 'आइडिया ऑफ इंडिया' कहते हैं. आज देश में मतदाताओं का विशाल युवा वर्ग ऐसा है, जिसने कांग्रेसी मूल्यों के पराभव, पार्टी के क्षरण और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के दौर में आंखें खोली हैं. इसी दौरान भाजपा और आरएसएस के विविध संगठनों के जरिये कट्टर हिंदुत्व एवं उग्र राष्ट्रवाद का विचार तेजी से फैला है.

इस पीढ़ी को सही-सही पता ही नहीं कि कांग्रेस किन-किन मूल्यों की पोषक रही है. उदाहरण के लिए, जब भाजपा की तरफ से नेहरू का छवि-मर्दन किया गया, तब कांग्रेस यह बताने में विफल रही कि नेहरू की इस देश को वास्तविक देन क्या है.

सशक्त प्रतिपक्ष बनने या सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को पहले अपनी 'कांग्रेसियत' पहचाननी होगी. उसके पास स्वतंत्रता आंदोलन और इस विविधतापूर्ण देश की बहुलता के सम्मान की विरासत है. उन्हीं मूल्यों के कारण ही आज उसकी और भी ज्यादा जरूरत है.

सशक्त प्रतिपक्ष बनने या सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को पहले अपनी 'कांग्रेसियत' पहचाननी होगी. उसके पास स्वतंत्रता आंदोलन और इस विविधतापूर्ण देश की बहुलता के सम्मान की विरासत है.

बोधि वृक्ष

अति का सामंजस्य

बहुत खाना, भूख से ज्यादा खाना बुरा है. इसी प्रकार बिल्कुल न खाना, या भूखे रहना भी बुरा है. अति का भोग बुरा है, पर अमर्यादित तप भी बुरा है. अधिक विषयी क्षीण होकर असमय में ही मर जाते हैं, पर जो अमर्यादित अतिशय तप करते हैं, शरीर को अत्यधिक कस डालते हैं, वे भी दीर्घजीवी नहीं होते. अतिका कंजूस होना ठीक नहीं, पर इतना दानी होना भी किस काम का कि कल खुद को ही दाने-दाने का मोहताज बनना पड़े. आलस्य में पड़े रहना हानिकारक है, पर सामर्थ्य से अधिक श्रम करते रहकर जीवनी शक्ति को समाप्त कर डालना भी लाभदायक नहीं है. कुबेर बनने की तृष्णा में पागल बन जाना या कंगाली में दिन काटना दोनों ही स्थितियां अवांछनीय हैं. नित्य मिठाई ही खाने को मिले, तो उससे अरुचि के साथ-साथ दस्त भी शुरू हो जायेंगे. भोजन में मीठे की मात्रा बिल्कुल न हो तो चमड़ी पीली पड़ जायेगी. बहुत घी खाने से मंदाग्नि हो जाती है, पर यदि बिल्कुल भी घी न मिले, तो खून खराब हो जायेगा. बिल्कुल न पढ़ने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता, पर दिन-रात पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं. कट्टर, असहिष्णु, सिद्धांतवादी बनने से काम नहीं चलता. दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है. अंधभक्त बनना या अविश्वासी होना दोनों ही बातें बुरी हैं. विवेकपूर्वक हंस की भांति नीर क्षीर का अन्वेषण करते हुए ग्राह्य और अग्राह्य को पृथक करना ही बुद्धिमानी है. देशकाल और पात्र के भेद से नीति व्यवहार और क्रिया पद्धति में भेद करना पड़ता है, नहीं तो हम अतिवादी कहे जायेंगे. अतिवादी-आदर्श तो उपस्थित कर सकते हैं, पर नेतृत्व नहीं कर सकते. आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी प्रगति उसी ओर होनी चाहिए, पर सावधानी से. कड़े कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है. मजबूत व्यक्तित्व धैर्यवानों का होता है. नियमितता, दृढ़ता एवं स्थिरता के साथ कार्य करते रहनेवाले व्यक्तियों द्वारा ही उपयोगी संतुलित कार्यों का संपादन होता है.

पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य

बच्चों के प्रति अपराध पर लगे अंकुश

अशोक कुमार पांडेय
लेखक
ashokk34@gmail.com

अलीगढ़ के टप्पल में ढाई वर्षीया बच्ची की जघन्य हत्या और कठुआ के गैंगरेप तथा हत्या कांड पर हाल में विशेष अदालत के फैसले के बाद से सोशल मीडिया में बच्चों के प्रति अपराधों पर चर्चा फिर शुरू हो गयी है. बीते हफ्तेभर से कम समय में लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मेरठ, बेगुसराय सहित कई शहरों से ऐसी घटनाओं की खबरें आयीं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन चर्चाओं के पार बच्चों के साथ हिंसा और खासतौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं. इन खबरों से समाचार माध्यम इस कदर भरे हुए हैं कि धीरे-धीरे ये सामान्य सी होती जा रही हैं और हम एक बीमार और हिंसक समाज बनते जा रहे हैं.

आंकड़ों की बात करें, तो साल 2001 से 2016 के बीच बच्चों के विरुद्ध अपराध के जो मामले दर्ज हुए, ध्यान दें- जो मामले दर्ज हुए, उनमें 889 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साल 2001 में 10,814 मामले दर्ज हुए. इनकी संख्या 16 साल में बढ़कर 5,95,089 हो गयी. इसी दौर में बच्चों के विरुद्ध अपराध के लंबित मामलों की संख्या 21,233 थी, जो 2016 में 11 गुना बढ़कर 2,27,739 हो गयी. केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 2016 के बीच बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं में 400 प्रतिशत का इजाफा हुआ. इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में रोज 106 रेप के मामले दर्ज किये गये. बच्चों के अपहरण और हत्या के मामलों में भी इस दौर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं सबसे अधिक दर्ज की गयीं. दुखद यह है कि इस परिघटना के खिलाफ कोई व्यापक जनमत बनने, सामाजिक आंदोलन उभरने या शासकीय स्तर पर किसी बड़ी पहलकदमी की जगह ऐसे अपराध अब रूटीन में शामिल होते जा रहे हैं और यह 'न्यू नॉर्मल' हमारी संवेदनाओं को एकदम नहीं झकझोरता. इसका उदाहरण अलीगढ़ की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रकाश शाही का वह बयान है, जिसमें उन्होंने इसे छोटी-मोटी घटना बताया. हालांकि, ऐसे बयान पहले भी आते ही रहे हैं.

किसी भी दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, ऐसी घटनाएं एक-दो कॉलम में दबी हुई मिल जाती हैं. चर्चा तब होती है, जब उसमें धर्म या कोई और एंगल जुड़ जाये. अलीगढ़ या कठुआ की घटना की इतनी चर्चा के मूल में भी यही है. हालत यह है कि कठुआ पर आये निर्णय को भी प्रतिष्ठा के प्रश्न जैसा बना लिया गया है. यह संवेदनहीनता परिवारों और समाज के भीतर बढ़ती अजनबियत और हिंसक प्रवृत्तियों के साथ मिलकर हमारे समाज को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बनाते जा रहे हैं. अध्ययन बताते हैं कि बच्चों के साथ होनेवाले यौन अपराधों में नब्बे फीसद परिवारों के भीतर या अत्यंत परिचित लोगों द्वारा किये जाते हैं. अभी लखनऊ में हुई घटना में अपराधी ने अपने घर छुट्टियां मनाने आयी एक रिश्तेदार बच्ची के साथ बलात्कार किया! चूंकि ऐसे लोगों पर बच्चों के माता-पिता भरोसा करते हैं, तो उनके लिए अपराध आसान हो जाता है और अक्सर ऐसी घटनाओं को इज्जत के नाम पर रिपोर्ट भी नहीं किया जाता. इसके अलावा परिवारों के आपसी विवादों का शिकार भी कई बार बच्चे ही बनते हैं, जैसा कि अलीगढ़ की घटना में हुआ.

इन घटनाओं पर राजनीति करने की जगह समाज और कानून, दोनों स्तरों पर व्यापक पहल की जरूरत है. निर्भया कांड के बाद लगा था कि शायद सरकारें अब ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेंगी, लेकिन कुछ शुरुआती शोर-शराबे के बाद सब कुछ वैसे का वैसा ही रह गया है. बच्चों और अभिभावकों दोनों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर ऐसी घटनाओं की संभावना कम की जा सकती है. दीर्घकालिक समाधान के लिए समाज में खासकर पुरुषों के बीच जेंडर मुद्दों पर गहन सेंसिटाइजेशन (संवेदीकरण) की जरूरत है. स्कूलों के स्तर से ही लड़कों की जेंडर ट्रेनिंग की जानी चाहिए और समाज के भीतर व्याप्त पितृसत्तात्मक मूल्यों को धीरे-धीरे खत्म किये जाने की कोशिश करनी चाहिए. मध्यवर्गीय रिहाइशों में तो ढेरों इंतजाम होते हैं, लेकिन निम्न मध्यवर्गीय इलाकों और झुग्गी-झोपड़ियों तथा ग्रामीण इलाके अभाव में रहते हैं. इसलिए इन जगहों में रोशनी, खेल के मैदानों, क्रेच आदि की व्यवस्था के साथ वहां अभिभावकों तथा बच्चों की काउंसलिंग और ट्रेनिंग पर जोर देना चाहिए, जिससे बच्चे अपराधियों की मंशा भांप सकें और माता-पिता उनकी आरंभिक शिकायतों को समझ सकें.

पॉक्सो जैसे मजबूत कानून के बावजूद अगर अपराधी बेखौफ हैं, तो केवल कड़े कानून से काम नहीं चलनेवाला, अब जरूरत है शीघ्र न्याय दिलाये जाने की. एक तरीका बच्चों के विरुद्ध होनेवाले सभी अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का हो सकता है. ऐसे कोर्ट गठित किये जाने और इनसे जुड़े लोगों को जेंडर तथा बाल मनोविज्ञान के विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है. इन सब सम्मिलित प्रयासों से ही ऐसी भयावह घटनाओं पर लगाम लग सकती है.

बच्चों पर हो रहे अपराधों पर रस्मी भावुकता से बाहर आकर बड़ी पहलकदमी की जरूरत है. लेकिन, विकास के नये-नये सपने देख रहा देश अगर अपने चुनावों में औरतों और बच्चों को मुद्दा नहीं बना पाता, अगर ऐसे मामलों में राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप में उलझ जाता है, तो विकास के वे सपने दागदार रह जाने के लिए अभिशप्त हैं.

पॉक्सो जैसे मजबूत कानून के बावजूद अगर अपराधी बेखौफ हैं, तो केवल कड़े कानून से काम नहीं चलनेवाला, अब जरूरत है शीघ्र न्याय दिलाये जाने की. एक तरीका बच्चों के विरुद्ध होनेवाले सभी अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का हो सकता है.

आपके पत्र

विमान खोजने में विलंब

अरुणाचल प्रदेश में 3 जून को गुम हुए भारतीय वायु सेना के 'एएन 32' विमान का मलबा आखिर आठ दिनों के बाद दिखाई दिया. विमान का पता न चलना चिंता की बात बन गयी थी. विमान के बारे में जानकारी देने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम देने की नौबत आ गयी थी. दरअसल उपग्रह पर आधारित आधुनिक प्रौद्योगिकी बहुत ही आगे बढ़ने के बावजूद विमान का पता लगाने में तुरंत सफलता नहीं मिली. इसके क्या कारण हो सकते हैं. 2016 के जुलाई महीने में चेन्नई से पोर्ट ब्लेअर जाने वाला वायु सेना का 'एएन 32' विमान भी लापता हुआ था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है. हैरानी की बात है कि इसी तरह के विमान ही लापता कैसे होते हैं ? यह बात समझ के बाहर है कि जो देश पड़ोसी राष्ट्र में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, वह अपने लापता विमान को खोज नहीं सकता. इसके कारण के तह में जाने की जरूरत है.

अनिल रा. तोरणे, पुणे, महाराष्ट्र

शंघाई सहयोग संगठन का महत्व

आगामी 13 एवं 14 जून को किर्गिस्तान की राजधानी 19वां शंघाई सहयोग संगठन का सम्मलेन होने जा रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित इसके आठ स्थायी सदस्य देश हिस्सा लेने वाले हैं. इस बार का मुद्दा है आपसी व्यापार, अफगानिस्तान, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं वैश्विक आतंकवाद. अपने देश का मुख्य मुद्दा भी आतंकवाद ही होगा. मगर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश को आतंकवाद के नाम पर सीधे हमला नहीं किया जायेगा. इसका मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उस सम्मलन में होंगे, जिन पर कोई आरोप नहीं लगाया जायेगा. राष्ट्रसंघ भी आजतक आतंकवाद को परिभाषित ही नहीं कर पाया है. इस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री का रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के जिनपिंग से बातचीत हो सकती है. इस सम्मेलन की उपयोगिता इसकी समाप्ति के बाद ही पता चल सकेगा.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

आपराधिक प्रवृत्ति वाले कार्यकर्ता

राजनीति के अपराधीकरण को लेकर लंबे समय से चिंता जतायी जा रही है, मगर इसे किसी भी राजनीतिक दल ने गंभीरता से नहीं लिया है. यही वजह है कि हर चुनाव के बाद नगर निगम से लेकर संसद तक में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की पैठ कुछ बढ़ी हुई दर्ज होती है. इस तरह हर राजनीतिक दल में कहीं न कहीं इसे लेकर स्वीकार्यता है कि बाहुबल और हिंसा के जरिये अपना दबदबा बनाया जा सकता है. इसलिए हर राजनीतिक दल आपराधिक प्रवृत्ति वाले अपने कार्यकर्ताओं के दोष को छिपाने का प्रयास करता दिखता है. जाहिर है बंगाल की हिंसा के पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही है. अगर पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व हिंसा के खिलाफ होते, तो वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने में जुटते. शीर्ष नेताओं की पहल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है.

डॉ हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर

कुछ अलग

यात्राओं का उद्देश्य

कविता विकास
लेखिका
kavitavikas28@gmail.com

गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में अब थोड़े ही दिन बचे हैं. अपनी यात्राओं से लोग लौट रहे हैं. पर जिन्हें पहले टिकट नहीं मिला था, वे अब जाने को तैयार हैं. हर जगह खचाखच भीड़ और ऊपर से गरमी की भयावहता. इस समय अगर ट्रेनें लेट चलती हैं, तब यात्रियों की हालत का अंदाजा लगाइये. कितनी कोफ्त होती है! गर्म हवाएं और पसीने से तर-ब-तर औरत, बच्चे और बूढ़े.

इत्तेफाकन एक प्लेटफॉर्म पर मेरी मौजूदगी थी, जहां मैंने सामाजिकता का एक नया आयाम देखा. फर्श पर प्लास्टिक की चादर पर एक नामी कंपनी के बड़े अधिकारी सपरिवार लेटे हुए थे, जिन्हें एसी के बिना शायद ही रहने की आदत हो. प्लेटफॉर्म की धूल भरी गरमी में अपनी नातिनों के साथ यात्रा की यादें शेयर करते हुए वे बड़ी सहजता से ठहाके लगा रहे थे. दूसरी ओर बरेली का एक किसान परिवार अपनी तीन बेटियों के साथ दार्जिलिंग जा रहा था. एक बंगाली लड़की अपनी मां को केदारनाथ घुमाने ले जा रही थी. कहीं जाने का जोश था, तो कहीं लौटने की बेसब्री. इरादे इतने मजबूत थे कि 44-45 डिग्री तापमान उन पर हावी नहीं हो रहा था.

यात्राओं का मकसद भी यही है. कुछ नया सीखने और कुछ नया देखने का उमंग सभी विषमताओं पर भारी होता है. हम जिस दुनिया को लड़कियों के लिए महफूज नहीं मानते हैं, उसी दुनिया में एक बेटी अपनी मां को तीर्थ कराने ले जा रही है. कितना कुछ अलग है आम धारणा से. धूप, गरमी, हवा, तूफान सब अपनी जगह हैं, पर आदमी की इच्छाशक्ति अपनी जगह. यात्राएं अपनी इच्छाशक्ति पर विजय पाने की एक छोटी सी कोशिश हैं, क्योंकि इस समय होनेवाली घटनाओं पर हमारा वश नहीं चलता.

सुख पाने से बड़ा ध्येय सुख में लिपटी खुशी को पाना होता है. जीवन की आपाधापी ने हमें सुख के करीब तो कर दिया है, पर आनंद से दूर कर दिया है. दिन भर मशीन बना मनुष्य रात में थक कर सो जाता है. इसलिए यात्राएं सुकून भरा लम्हा देती हैं, जिसमें परिवार का सान्निध्य होता है या दोस्तों की नजदीकियां. यात्रा के समय किसी की तबियत बिगड़ जाये, या किसी की पॉकेटमारी हो जाये या कोई किसी हादसे का शिकार हो जाये, तो मदद के लिए उठते हाथ आदमियत की पहचान कराते हैं. यह इस बात को भी बतलाता है कि भौतिकवादी समाज में अभी भी संवेदनशीलता जीवित है.

मुझे याद है, एक कवि सम्मेलन में आ रही एक कवयित्री की अटैची चोरी हो जाती है, जिसमें उनके कपड़े वगैरह थे. जब वह आयीं, तो किसी ने पहनने के लिए साड़ी दी, तो किसी ने कॉस्मेटिक्स. उन्हें लौटने के पैसे भी दिये गये. यथासंभव मदद देखकर उनकी आंखें नम हो गयीं. यही तो सामाजिकता है. हम आज के युग में सबसे अलग-थलग भले ही रहते हों, पर जरूरत पड़ने पर जब हम किसी के काम आते हैं, तो यह जीवन की एक उपलब्धि बन जाती है. यह नेक काम हमें अपने ऊपर गर्व करने का मौका देता है.

देश दुनिया से

जलवायु परिवर्तन से लड़ने की प्रतिबद्धता

कोई भी द्वीप ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान देते हैं, लेकिन इसके विनाशकारी प्रभाव से सबसे पहले पीड़ित होनेवाले यही हैं. विनाशकारी प्रभाव से इन द्वीपों को बचाने के लिए सबसे कम उपाय किये गये हैं. बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में, समृद्ध औद्योगिक देशों ने इस उपग्रह को गर्म करना जारी रखा है. समुद्र जल का बढ़ता स्तर बार-बार इन द्वीपों पर कहर बरसा रहा है. इतना ही नहीं, अस्वाभाविक रूप से गर्म हो रहे मारिया और इरमा जैसे विनाशकारी तूफान, ऐतिहासिक मानदंडों से परे जाकर बेहद मजबूत हो गये. इस तूफान के कारण न सिर्फ घर और बिजली व्यवस्था बरबाद हुई, बल्कि अनगिनत लोग भी मारे गये. कल तक ऐसे विनाशकारी तूफान कभी-कभार ही आते थे, लेकिन आज इनकी बारंबारता बढ़ जाने से छोटे द्वीपों में आनेवाली तबाही के मद्देनजर एकजुटता देखी जा रही है. इस तबाही से बचने के लिए हम लचीलेपन की एक नयी भावना भी साझा कर रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. विशेष रूप से, हमारे द्वीप अभिनव स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए आदर्श प्रयोगशालाओं के रूप में काम कर सकते हैं.

माइक इमान

कार्टून कोना

दि न्यूयार्क टाइम्स में अब नहीं छपेगा राजनीतिक कार्टून

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है